पुलिस आयुक्त एवं अन्य

विरूद्ध

श्रीमती सी. अनिता

23 अगस्त 2004

[अरिजीत पसायत और सी. के. ठाकर जे.जे.]

आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैतों, नशीली दवाओं के अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार अपराधियों और भूमि कब्ज़ा करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986-धारा 3 (2) - हिरासत के तहत हिरासत आदेश में उल्लेख किया गया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक हिस्ट्रीशीटर था, 30 मामले दर्ज किए गए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और दो विशिष्ट उदाहरणों में उनके कृत्यों की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया - हिरासत के खिलाफ रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया गया - अपील पर, माना गया: मामले के तथ्यों में हिरासत का आदेश सही तरीके से दिया गया है - अदालत अपनी राय के स्थान पर अपनी राय नहीं दे सकती हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी जब हिरासत के आधार सटीक, प्रासंगिक, अनुमानित और प्रासंगिक हों।

'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भेद पर चर्चा की गई।

'निवारक हिरासत'- अर्थ, प्रकृति और धारण का उद्देश्य: यह निवारक है और दंडात्मक नहीं है- यह संदेह का क्षेत्राधिकार है-हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिवादी (हिरासत) के पति को आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स, डकैतों, नशीली दवाओं के अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार अपराधियों और भूमि कब्जा करने वालों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) के तहत हिरासत में लिया गया था। अपीलकर्ता ने इस आधार पर रिट याचिका दायर की थी कि हिरासत के आदेश में उजागर किए गए कथित कृत्यों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है; और चूंकि उल्लिखित घटनाएं बहुत पहले हुई थीं, इसलिए हिरासत आदेश की गारंटी देने के लिए कोई लाइव लिंक नहीं था। उच्च न्यायालय ने हिरासत के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भले ही हिरासत आदेश में उजागर की गई घटनाओं के साथ निकटता थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि उन कृत्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रभावित किया था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिरासत में लिए गए लोगों की

गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थीं, और हिरासत आदेश में उल्लिखित विशिष्ट दो उदाहरणों के अलावा, लगभग 30 मामले हिरासत में लिए गए व्यक्ति के विरुद्ध एक संस्थित किया गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. निवारक हिरासत एक अग्रिम उपाय है और किसी अपराध से संबंधित नहीं है, जबकि आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने के लिए है। वे समानांतर कार्यवाही नहीं हैं। निवारक निरोध के कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि केवल निवारक है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब कार्यपालिका आश्वस्त हो जाती है कि इसे रोकने के लिए ऐसी हिरासत आवश्यक है व्यक्ति को कुछ वस्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तरीके से कार्य करने से हिरासत में लिया गया है जो संबंधित कानून द्वारा निर्दिष्ट हैं। कार्यपालिका की कार्यवाही किसी व्यक्ति को केवल एहतियाती तौर पर हिरासत में लेना आम तौर पर मामला है इसे आवश्यक रूप से कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह है आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमों को विस्तृत रूप से निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है तरीके जिसका पालन न करने पर हिरासत में लिया जाना चाहिए। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी किसी भी सामग्री और किसी भी जानकारी पर कार्यवाही कर सकता है कि यह इसके पहले हो सकता है। ऐसी सामग्री और जानकारी केवल कार्यवाही करने के

लिए पर्याप्त मजबूत संदेह का आधार हो सकती है, लेकिन कानूनी सबूत के परीक्षणों को पूरा नहीं कर सकती है, जिसके आधार पर ही अपराध के लिए दोषसिद्धि संभव होगी। इस क्षेत्राधिकार को कभी-कभी संदेह का क्षेत्राधिकार भी कहा गया है। एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी ओर एक व्यवस्थित समाज की जरूरतों के बीच सही संतुलन बनाकर कानून को उचित ठहराया जाना चाहिए। [705-सी-जी; 706-ए; 706-सी]

2. जबकि एक अभिव्यक्ति 'कानून और व्यवस्था' का दायरा काफी व्यापक है क्योंकि कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है। 'सार्वजनिक व्यवस्था' का दायरा सीमित है, और सार्वजनिक व्यवस्था केवल ऐसे उल्लंघन से प्रभावित हो सकती है जो बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित करती है। कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच का अंतर समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। यदि कोई उल्लंघन अपने प्रभाव में जनता के व्यापक स्पेक्ट्रम से अलग सीधे तौर पर शामिल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, तो यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था के सामान्य रखरखाव से कुछ अधिक है। शांति के प्रत्येक उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। विकार एक व्यापक स्पेक्ट्रम है जिसमें एक छोर पर छोटी गड़बड़ी और दूसरे छोर पर सबसे गंभीर और

विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं। कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर केवल अधिनियम की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है बल्कि समाज पर इसकी पहुंच की डिग्री और सीमा में भी निहित है। कानून और व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है जैसे सार्वजनिक व्यवस्था राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है। [707-डी-जी; 708-सी-डी; 709-सी-डी; 709-एफ-जी]

कानू बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर (1972) एससी 1656; डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1966] 1 एससीआर 709; किशोरी मोहन बेरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1972] 3 एससीसी 845; सी. पुष्कर मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1969] 2 एससीआर 635; अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1970] 3 एससीआर 288; नागेंद्र नाथ मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1972] 1 एससीसी 498; बाबुल मित्रा उर्फ अनिल मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, [1973] 1 एससीसी 393; मिलन बनिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एससीसी 504; कुसो साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1974] 1 एससीसी 185; हरप्रीत कौर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1992] 2 एससीसी 177; टी.के. गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य, [2000] 6

एससीसी 168 और महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद। याकूब, [1980] 2 एससीआर 1158, पर भरोसा किया गया।

3. हिरासत के आदेश से पता चलता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर था जिसके खिलाफ 30 से अधिक मामले कायम किए गए थे। दो विशिष्ट उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया जो उसके कृत्यों की गंभीरता का संकेत देते थे। जब हिरासत के आधार सटीक, प्रासंगिक, अनुमानित और प्रासंगिक हों तो न्यायालय हिरासत प्राधिकारी की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकता है। यहाँ भी यही स्थिति है. कोई अस्पष्टता या बासीपन नहीं है. घटनाओं को हिरासत के आधार पर उजागर किया गया है और इसके प्रभाव के बारे में निश्चित संकेत दिए गए हैं, जो सटीक रूप से बताए गए हैं। दोनों घटनाएं हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं कि कैसे बंदी के कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थे। [709-एच; 710-ए; 710-सी-ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 922/2004।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. में संख्या 16195/2003 में दिनांक 11.9.2003 को निर्णय और आदेश से। श्रीमती डी. भारती रेड्डी, बी. विकास और जी. वेणुगोपाल, अपीलकर्ता के लिए ।

राधाकृष्णन, सुश्री. पूजा नानेकर, कु. प्रिया माधवन और उदय मैसर्स के लिए कुमार सागर। प्रतिवादी के लिए लॉयर्स निट एंड कंपनी।

न्यायालय का निर्णय बी द्वारा सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.: छुट्टी स्वीकृत।

आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस आयुक्त, हैदराबाद शहर (संक्षेप में 'आयुक्त') द्वारा दिनांक 15.7.2003 को पारित हिरासत के आदेश को रद्द करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाता है। चिन्नाबोइना शंकर @ सी. शंकर (इसके बाद 'हिरासत' के रूप में संदर्भित) को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया। हिरासत का आदेश आंध्र प्रदेश बूटलेगर्स की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम की धारा 3 की उप-धारा (2) डी के संदर्भ में पारित किया गया था। डकैत, नशीली दवाओं के अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी और भूमि-कब्जा करने वाले अधिनियम, 1986 (संक्षेप में 'अधिनियम')। बंदी की पत्नी श्रीमती सी. अनीता ने वैधता पर सवाल उठाते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आवेदन दायर किया। हिरासत

के आदेश का। रिट याचिका में प्राथमिक अनुमान यह था कि हिरासत के आधार पर उजागर किए गए कथित कृत्यों को किसी भी तरह से सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने और/या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि हिरासत के आधार पर जिन घटनाओं का संदर्भ दिया गया था, वे कथित तौर पर बहुत पहले हुई थीं और हिरासत के आदेश की गारंटी देने के लिए कोई लाइव लिंक नहीं था। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि एफ की हिरासत के आदेश में उजागर की गई घटना से निकटता थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वे कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रभावित कर रहे थे। आगे यह माना गया कि भले ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गुंडा और भूमि हड़पने वाला माना गया हो, लेकिन यह निवारक हिरासत के लिए पर्याप्त नहीं है। तदनुसार हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। हिरासत के आधार में न केवल दो विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कैसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ लगभग 30 मामले स्थापित किए गए और उसकी एच गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव ने सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले आतंक की भावना पैदा की।

हिरासत के आदेश के पैराग्राफ 3 का संदर्भ दिया गया था, जो विद्वान वकील के अनुसार यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि किस तरह से बंदी की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थीं।

जवाब में प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि लगाए गए आरोप अधिक से अधिक कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं लेकिन इसमें कोई सार्वजनिक व्यवस्था शामिल नहीं थी। हिरासत के आधार में उल्लिखित कथित घटनाएं हिरासत के आदेश जारी होने से बहुत पहले हुई थीं और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत के आदेश को रद्द करना उचित था। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, निवारक हिरासत के उद्देश्य और इरादे से निपटना उचित होगा। निवारक हिरासत एक अग्रिम उपाय है और यह किसी अपराध से संबंधित नहीं है, जबकि आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने के लिए होती है। वे समानांतर कार्यवाही नहीं हैं. निवारक निरोध के कानून का उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि केवल निवारक है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब कार्यपालिका आश्वस्त हो जाती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संबंधित कानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ वस्तुओं के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए ऐसी हिरासत आवश्यक है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने में कार्यपालिका की कार्यवाही केवल एहतियाती होती है, आम तौर पर मामले को कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आचरण के वस्तुनिष्ठ नियमों को

विस्तृत तरीके से निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, जिसके अनुपालन में विफलता के कारण हिरासत में लिया जाना चाहिए। इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि को प्राथमिक महत्व माना जाता है, अपने विवेक के प्रयोग में काफी स्वतंत्रता के साथ। हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी किसी भी सामग्री और उसके सामने मौजूद किसी भी जानकारी पर कार्यवाही कर सकता है। ऐसी सामग्री और जानकारी केवल कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त मजबूत संदेह का आधार हो सकती है, लेकिन कानूनी सबूत के परीक्षणों को पूरा नहीं कर सकती है, जिसके आधार पर ही अपराध के लिए दोषसिद्धि संभव होगी। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की मौलिक आवश्यकता की बाध्यताएं, जिसके बिना नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी अधिकारों का आनंद उनके सभी अर्थ खो देगा, निवारक निरोध के कानूनों के लिए जी को औचित्य प्रदान करता है। निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानूनों का मानना है कि किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या राज्य की सुरक्षा या कमजोर वित्तीय आधार के लिए प्रतिकूल है, जो एच पर समान प्रवृत्तियों की संभावित भविष्य की अभिव्यक्तियों के उचित पूर्वानुमान के लिए संतुष्टि का आधार प्रदान करता है। अपराधी का वह हिस्सा. इस क्षेत्राधिकार को कभी-कभी संदेह का क्षेत्राधिकार भी कहा गया है। लोकतांत्रिक समाज की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों के संरक्षण की मजबूरियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के लिए मजबूर कर सकती हैं। थॉमस

जेफरसन ने कहा, "लिखित कानून का ईमानदारी से पालन करके अपने देश को खोना" को खोना होगा कानून स्वयं, जीवन, स्वतंत्रता और उन सभी के साथ जो हमारे साथ आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार जरूरतों के लिए बेतुके ढंग से बलिदान दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह निवारक हिरासत को सक्षम करने वाले कानून के लिए सैद्धांतिक क्षेत्राधिकार संबंधी औचित्य है। लेकिन प्रशासन का वास्तविक तरीका निवारक हिरासत के कानून का अत्यधिक महत्व है। कानून को एक ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी ओर एक व्यवस्थित समाज की जरूरतों के बीच सही संतुलन बनाकर उचित ठहराया जाना चाहिए। इन पहलुओं को भारत संघ बनाम मामले में उजागर किया गया था। अमृत लाल मनचंदा और अन्य, [2004] 3 एससीसी 75.

कुछ प्रावधान जिनकी प्रासंगिकता है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। धारा 2(बी) और 2(जी) क्रमशः 'बूट लेगर्स' और 'गुंडा' को परिभाषित करती हैं। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

> "2(बी) बूट लेगर्स' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है, जो आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी शराब नशीली दवा या अन्य नशीले पदार्थ का आसवन, निर्माता, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री या वितरण करता है और उसके तहत बनाए

गए नियम, अधिसूचनाएं और आदेश या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून का उल्लंघन करते हुए, या जो जानबूझकर कोई पैसा खर्च करता है या लागू करता है या किसी जानवर, वाहन, जहाज या अन्य वाहन या किसी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है ऊपर उल्लिखित किसी भी कार्य को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाने या समर्थन करने में, या जो किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए उकसाता हो; 2(जी)-गुंडा' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, अध्याय XVI या अध्याय XVII या अध्याय XXII के तहत दंडनीय अपराधों को आदतन करता है, या करने का प्रयास करता है या ऐसा करने के लिए उकसाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860।"

धारा 3 की उपधारा (2) जिसके सन्दर्भ में आदेश निरोध पारित कर दिया गया है इस प्रकार पढ़ता है बशर्ते कि इस उपधारा के तहत सरकार द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि पहली बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार, यदि पूर्वोक्त रूप से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे आदेश को बढ़ाने के लिए संशोधन कर सकती है। समय-समय पर ऐसी अवधि किसी भी समय एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या बंदी की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थीं। जबकि अभिव्यक्ति 'कानून और व्यवस्था' का दायरा व्यापक है क्योंकि कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है। 'सार्वजनिक व्यवस्था' का दायरा सीमित है, और सार्वजनिक व्यवस्था केवल ऐसे उल्लंघन से प्रभावित हो सकती है जो समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। सार्वजनिक व्यवस्था पूरे देश या यहां तक कि एक निर्दिष्ट इलाके को ध्यान में रखते हुए समुदाय के जीवन की सम गति है। कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच का अंतर समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है। यह समुदाय के जीवन की सम गति को बाधित करने की अधिनियम की क्षमता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाती है। यदि कोई उल्लंघन अपने प्रभाव में जनता के व्यापक स्पेक्ट्रम से अलग सीधे तौर पर शामिल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, तो यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। यह अव्यवस्था के एक विशेष विस्फोट से फैली आतंक लहर की लंबाई, परिमाण और तीव्रता है जो इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाले अधिनियम से 'कानून और व्यवस्था' से संबंधित अधिनियम के रूप में अलग करने में मदद करती है। पूछने का प्रश्न यह है; "क्या इससे समुदाय के वर्तमान जीवन में अशांति पैदा होती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है या क्या यह

समाज की शांति को छोड़कर केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है"? इस सवाल का सामना हर हाल में इसके तथ्यों पर करना होगा.

यदि, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वे आदेश द्वारा कर सकते हैं लिखित रूप में, निर्देशित करें कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हैं, तो उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं:

"सार्वजनिक व्यवस्था" वह है जिसे फ्रांसीसी 'ऑर्ड्रे पब्लिक' कहते हैं और यह कानून और व्यवस्था के सामान्य रखरखाव से कुछ अधिक है। यह निर्धारित करने के लिए अपनाया जाने वाला परीक्षण कि क्या कोई कार्य कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, यह है: क्या यह समुदाय के वर्तमान जीवन में गड़बड़ी पैदा करता है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है या क्या यह केवल व्यक्तिगत छोड़ने पर प्रतिबंध को प्रभावित करता है समाज की शांति अबाधित रहे? (देखें कनु बिस्वास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर (1972) एससी 1656।

"सार्वजनिक व्यवस्था" सार्वजनिक सुरक्षा और शांति का पर्याय है: "यह राष्ट्रीय उथल-पुथल, जैसे क्रांति, नागरिक संघर्ष, युद्ध, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले स्थानीय महत्व के उल्लंघन से जुड़ी अव्यवस्था की अनुपस्थिति है"। यदि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो इससे सार्वजनिक अव्यवस्था अवश्य होगी। प्रत्येक शांति भंग से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती.. जब दो शराबी झगड़ते और लड़ते हैं तो अव्यवस्था होती है लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती। उनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है, लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि वे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाल रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से भी अव्यवस्था को रोका जा सकता है, लेकिन अव्यवस्था एक व्यापक स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक छोर पर छोटी गड़बड़ी और दूसरे छोर पर सबसे गंभीर और विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं (देखें डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1996] 1 एससीआर 709.

'सार्वजनिक व्यवस्था', 'कानून और व्यवस्था' और 'राज्य की सुरक्षा' काल्पनिक रूप से तीन संकेंद्रित वृत्त बनाएं, जिनमें से सबसे बड़ा कानून का प्रतिनिधित्व करता है और आदेश, अगला सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा प्रतिनिधित्व करता है राज्य की

सुरक्षा. कानून का प्रत्येक उल्लंघन आवश्यक रूप से व्यवस्था को प्रभावित करेगा, लेकिन कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई कार्य आवश्यक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी तरह, कोई कार्य सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करे। सच्ची परीक्षा प्रकार नहीं है, बल्कि कार्य की क्षमता है। एक कार्य केवल व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, जबकि दूसरा, समान प्रकार का होते हुए भी, इतना प्रभाव डाल सकता है कि यह समुदाय के जीवन की सम गति को बिगाड़ देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, इस अर्थ में कि कोई अधिनियम एक ही समय में दो अवधारणाओं के अंतर्गत नहीं आ सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई कार्य सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। (देखें किशोरी मोहन बेरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1972] 3 एससीसी 845; पुष्कर मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1969] 2 एससीआर 635; एच अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 3 एससीआर 288; नागेंद्र नाथ COMMR. पुलिस बनाम सी. अनीता [पसायत, जे.] मंडल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिम बंगाल राज्य, [1972] । एससीसी 498)।

अरुण घोष के मामले (सुप्रा) में 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर को संक्षेप में बताया गया है। उस निर्णय के अनुसार 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर "समाज पर विचाराधीन अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा में से एक है"। न्यायालय ने बताया कि "कार्य अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। इसकी गुणवत्ता में यह भिन्न नहीं हो सकता है लेकिन इसकी क्षमता में यह बहुत भिन्न हो सकता है"। (देखें बाबुल मित्रा उर्फ अनिल मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, [1973] 1 एससीसी 393, मिलन बनिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एससीसी 504।

कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर केवल अधिनियम की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि समाज पर इसकी पहुंच की डिग्री और सीमा में भी निहित है। प्रकृति में समान, लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए कार्य अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। एक मामले में यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए केवल कानून और व्यवस्था की समस्या को छूता है, जबकि दूसरे में यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, कार्य अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। अपनी गुणवत्ता में यह अन्य समान कृत्यों

से भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी क्षमता में, यानी समाज पर इसके प्रभाव में, यह बहुत भिन्न हो सकता है। दोनों अवधारणाओं में अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखा है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि चोरी और हमले के छिटपुट और असंगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था के मामले नहीं हैं क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन के समान प्रवाह को प्रभावित नहीं करते हैं। कानून का उल्लंघन कुछ हद तक अव्यवस्था को जन्म देने के लिए बाध्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि कानून के हर उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था हो। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े पैमाने का प्रतिनिधित्व करती है जिसके भीतर अगला घेरा सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा घेरा राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। "कानून और व्यवस्था" "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है। न्याय "सार्वजनिक व्यवस्था" के रूप में "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता वाले विकारों को समझती है। (देखें कुसो साह बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1974] 1 एससीसी 185, हरप्रीत कौर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1992] 2 एससीसी 177; टीके गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य, [2000] 6 एससीसी 168 और महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, [1980] 2 एससीआर 1158।

हिरासत के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक हिस्ट्रीशीटर था, जिसके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। दो ऐसे विशिष्ट उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया जो उसके कृत्यों की गंभीरता का संकेत देते थे। हिरासत के आधार के पैराग्राफ 3 और 6 इस प्रकार हैं:

3- क्षेत्र में आपके गैरकानूनी कृत्यों से जनता के मन में भय व्याप्त हो रहा है और कानून का पालन करने वाले नागरिक डर के कारण प्लॉट/जमीन खरीदने और मकान बनाने से डर रहे हैं और वे किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए आगे आने से भी डरते हैं पुलिस आपके विरुद्ध या कोई अभ्यावेदन करे।

6- इस प्रकार, आप गुंडागर्दी, भूमि कब्ज़ा करने में लिप्त हैं और आपकी गतिविधियाँ जनता में असुरक्षा और भय की भावना पैदा कर रही हैं और इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल हैं।

जब हिरासत के आधार सटीक, प्रासंगिक, निकटतम और प्रासंगिक हों तो न्यायालय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकता है। यहाँ भी यही स्थिति है. कोई अस्पष्टता या बासीपन नहीं है. घटनाओं को हिरासत के आधारों के साथ-साथ उसके प्रभाव के निश्चित संकेत के साथ उजागर किया गया है, जिसे ऊपर उद्धृत

हिरासत के आधारों के पैराग्राफ 3 में सटीक रूप से बताया गया है। दोनों घटनाओं से पता चलता है कि किस तरह से बंदी जमीन खरीदने वाले से ई-पैसे की मांग कर रहा था और मांग पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये घटनाएँ हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं कि कैसे बंदी के कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल थे। इन पहलुओं पर उच्च न्यायालय के विद्वान वकील द्वारा विचार नहीं किया गया है बंदी ने प्रस्तुत किया कि यदि ऐसा है तो भी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और मामले को नए फैसले के लिए वापस भेजा जा सकता है। हमें ऐसी दलील में कोई दम नजर नहीं आता. हिरासत के आदेश का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ऐसा होने पर, हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं। बंदी को सजा की शेष अवधि काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तान सिंह चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।